एक राष्ट्रव्यापी अभियान के लिए पृष्ठभूमि नोट

हमें कोविड–19 से निपटने में अन्धविश्वास नहीं, विज्ञान से मदद मिलेगी।

.23 जुलाई 2020 को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (एआईडीडब्ल्यूए) क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी और प्रगतिशील मूल्यों, लोकतांत्रिक अधिकारों, लैंगिक न्याय व जीवन भर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए जीवन भर अनथक संघर्ष करने वाली कैप्टन लक्ष्मी सहगल की आठवीं पुण्यतिथि मना रहा है। वे 1981 में बने संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक थीं, और उन्होनें हिंदी क्षेत्र में संगठन बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । एक डॉक्टर के रूप में, यूपी के कानपूर में स्थित उनका क्लिनिक संगठन के लिए एक नोडल केंद्र था, जो उन महिलाओं को आकर्षित करता था जो चिकित्सा खर्च वहन करने में असमर्थ थी। इसके साथ–साथ यह जगह कार्यकर्ताओं की बैठकों व बातचीत के लिए अनुकुल जगह थी । हजारों भाग्यशाली बच्चों को उन्होंने अपने क्लिनिक में जन्म दिलवाया, परन्तु उनके माता पिता को चिकित्सा खर्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी।

अखिल भारतीय पीपुल्स साइंस नेटवर्क (एआईपीएसएन) जिसमें पूरे भारत में 37 संगठन शामिल हैं, डॉ लक्ष्मी सहगल के भारी योगदान को याद करने और मनाने में जनवादी महिला समिति के साथ शामिल हैं । गौरतलब है कि उन्होंने 1987 में सांइस नेटवर्क की स्थापना में एक अग्रणी भूमिका निभाई थी और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने व रूढ़िवाद के खिलाफ खिलाफ लड़ाई की चैंपियन रही हैं।

डॉ लक्ष्मी सहगल का जीवन और कार्य कोविड–19 महामारी के दौरा में और अधिक प्रासंगिक हो गया है जिसके दौरान रूढ़िवादी ताकतें अंधविश्वास और छद्म वैज्ञानिक मान्यताओं को फैलाने के लिए लोगों, विशेष रूप से महिलाओं के बीच भय का खेल रही हैं। .कई परंपरावादी प्रथाओं का कोविड–19 के इलाज या निवारक के रूप में इस्तेमाल करने की वकालत की जा रही है। महामारी के इस समय में संघ परिवार द्वारा रूढ़िवादी मूल्यों, सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और पितृसत्तात्मक धारणाओं को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रगतिशील और लोकतांत्रिक ताकतों द्वारा इसका एकजुट होकर विरोध किया जाना चाहिए।

विज्ञान का संदेश

कोविड–19 महामारी जनवरी 2020 में भारत में आई और शुरुआती दिनों से ही सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती पेश की जो अभी भी कोरोना वायरस के बारे में सीख रहे हैं । केरल को छोड़कर जिसने उल्लेखनीय रूप से दुनिया भर में

छाप छोड़ी, केंद्र सरकार और अधिकांश राज्य सरकारों ने एक सुसंगत, तर्कसंगत समझ को लोगों के समक्ष रखने व प्रभावी ढंग से संवाद कायम करने में काफी देरी की। खुद प्रधानमंत्री द्वारा अचानक बिना किसी योजना के लागू किए गए लॉक डाउन तथा बाद में दीए जलवाने, ताली व थाली बजाने आदि से बीमारी के फैलाव को रोकने में कोई मदद नहीं मिली।

इसमें आश्चर्य नहीं कि कोविड–19 से सुरक्षा और राहत हासिल करने की बेचैनी से पैदा हुई शून्यता को भरने के लिए लोग मिथकों और विश्वासों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें गर्म पानी पीना, धूप में खड़े होना, घर में कुछ खास पौधे उगाना आदि कई घरेलू उपचार शामिल हैं। अगर वैज्ञानिकों व लोगों के संगठनों और आंदोलनों के दबाव में, अधिक सुसंगत और विज्ञान आधारित सार्वजनिक संदेश लोगों तक नहीं पंहुचते हैं तो इस तरह के अपरीक्षित विश्वासों लोकप्रियता मिलती रहेगी। एआईएसपीएन और वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अन्य संगठन ही डब्ल्यूएचओ और आईसीएमआर के दिशा निर्देशों व स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय के आधार पर कोरोना वायरस के संबध में क्या करें और क्या नहीं की सही सूचनाएं जनता को देने में सबसे आगे है। कई लोकप्रिय प्रथाएं और घरेलू उपचार इसलिए भी स्वीकृति प्राप्त करते हैं क्योंकि 80 प्रतिशत मामलों में रोगी बिना किसी उपचार के ठीक हो जाता है।

इस बीच मुख्य चुनौती रूढ़िवादी ताकतों और निहित स्वार्थी तत्वों को इस अनिश्चितता का उपयोग करते हुए अपनी विचारधारा का प्रसार करने और मुनाफा कमाने से रोकने की है। यह अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। स्वयं के स्तर पर घरेलू या परंपरावादी उपचार करने की प्रवृति इस भ्रामक संदेश के साथ कि कोविड–19 के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है और सरकारों की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को तेजी से देकर सस्ती गुणवत्ताप्ररक चिकित्सा देखभाल प्रदान करने की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए प्रोतसाहित की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई उपचारात्मक एलोपैथिक दवा नहीं है। वैज्ञानिक और चिकित्सा समुदायों ने वायरस और इसके प्रभावों के बारे में बहुत कुछ सीखा है और इस ज्ञान को कोविड–19 के परीक्षण और उपचार में विशेष रूप से अस्पतालों में ऑक्सीजन या वेंटिलेटर के साथ या बिना इनके लागू कर रहे हैं। इसके अलावा, निश्चित उपचार और रोकथाम के लिए टीकों की खोज विशेष रूप से नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से वैज्ञानिक सत्यापन पर जोर देने के साथ जारी है ताकि सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित हो सके। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। दुर्भाग्य से, आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र के भीतर भी कुछ चीजें धकेली जा रही हैं। कॉर्पोरेट और सता में बैठे उसके चहेतों के हितों के लिए, मुनाफे या झुठे राष्ट्रीय गौरव के लालच से प्रेरित होकर वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में कटौती की जा रही है। अस्पतालों पर जल्दबाजी में टीका तैयार करने के जिए नैदानिक परीक्षणों में तेजी लाने का अनुचित दबाव शायद इसलिए बनाया

जा रहा कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से एक विजयी घोषणा की जा सके। वैज्ञानिक व चिकित्सा समुदायों तथा जागरूक लोगों के विरोध बाद ही इस मंशा से पीछे हटा गया है।

छद्म उपचार और झूठे प्रचार का मुकाबला

आयुर्वेद, होम्योपैथी या अन्य पारंपरिक योगों के नाम पर कोविड के इलाज के कुछ झूठे उपचार और नकली दावे किए जा रहे हैं। इनमें से किसी के पास इन परंपराओं के भीतर भी कोई आधार नहीं है और न ही वे किसी वैज्ञानिक परीक्षण से गुजरे हैं। फिर भी ऐसे कई दावों को प्रचारित करने की अनुमति दी गई है। यहां तक कि केन्द्र और कई राज्यों में कुछ मंत्रियों ने भी ऐसे दावे किए हैं। जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री या सरकार के प्रमुख प्रवक्ताओं को ऐसे दावों पर चुनौती दी गई, तो भी उन्हें सिरे से खारिज करने की बजाय यह कहा गया कि वे उन मंत्रियों या नेताओं की व्यक्तिगत मान्यताएं हो सकती हैं।

इस प्रवृति की वजह से बाबा रामदेव के पतंजलि समूह ने आयुर्वेदिक इलाज का बेशर्म दावा किया। राजनीतिक रूप से संघ परिवार से जुड़े बाबा द्वारा तैयार दवाई बिना किसी क्लिनिकल के ट्रायल के मुनाफे के लिए बाजार में उतार दी गई। जब वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और जागरूक नागरिकों द्वारा सार्वजनिक रूप से विरोध किया गया तो स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालयों को इस दावे को खारिज करने के लिए मजबूर होना पड़ा और यहां तक कि जादुई इलाज और उपचार के खिलाफ जल्द ही कानून लागू करने की घोषणा करनी पड़ी। इसके बावजूद भी, कई तथाकथित रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली और कोविड–19 से लोगों को लड़ने में मदद करने वाली दवाओं को प्रचारित किया जा रहा है तथा बड़ी चतुराई से इलाज की बजाए देखभाल शब्द का उपयोग किया जा रहा है।

छद्म वैज्ञानिक दावों को मान्यता मिल रही है क्योंकि ऐसी ताकतों का समर्थन करने वाली सताधारी पार्टी ऐसी धारणाओं को साथ लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए, लोगों को बालकनी या दरवाजों पर आकर ताली व थाली बजाने और बाद में दीए, मोमबती, मशालें या हल्के लैंप जलाने का आह्वान किया था जिसके बाद ट्विटर और सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टस की बाढ़ आ गई जिनमें दावा किया गया कि भारत द्वारा जलाए गए दीए नासा द्वारा अंतरिक्ष से देखे गए हैं, इन सार्वजनिक प्रदर्शनों से शक्तिशाली विकिरण या कंपन पैदा होगा जो कोरोना वायरस को नष्ट कर देगा। सरकार या संघ परिवार के किसी भी नेता द्वारा इन दावों में से किसी का खंडन करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। (यह कहने की जरूरत नहीं है कि वायरस चिंताजनक रूप से फैलता जा रहा है) इस तरह के दावों का इस्तेमाल ना केवल पीएम की महाशक्तियों को

बढ़ा–चढ़ा कर दिखाने के लिए किया जा रहा है, बल्कि समाज में विज्ञान, तार्किकता और आलोचनात्मक सोच के प्रभाव को कमजोर करने के लिए भी किया जा रहा है।

संघ परिवार और इससे जुड़ी ताकतों ने सांप्रदायिक जहर फैलाने के लिए भी कोविड–19 महामारी का इस्तेमाल किया है। निजामुद्दीन में एक बेहद खेदजनक सामूहिक धार्मिक सभा, का उपयोग महामारी फैलने के प्रमुख कारण के रूप में किया गया। एक विशेष धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को कई महीनों तक व्यवस्थित रूप से राक्षस के जौर पर प्रस्तुत किया गया। झूठी अफवाहें फैलाकर पूरे समुदाय को कलंकित करने का प्रयास किया गया कि इस सभा से निकले कोरोना संक्रमित लोग जानबूझकर वायरस फैलाने के लिए दूसरों पर थूक रहे हैं या इस समुदाय से संबंधित विक्रेताओं से सब्जियां खरीदना खतरनाक है आदि। साधारण तथ्य यह है, विज्ञान हमें सिखाता है, कि यह धर्म मायने नहीं रखता है, लेकिन वहां एक बड़ी सभा हुई थी, जिसमें शारीरिक दूरी या अन्य सावधानियों का ख्याल नहीं रखा गया। हाल ही में देश के सबसे लोकप्रिय मंदिर में हुई एक घटना जहां बड़ी संख्या में पुजारी और श्रद्धालु संक्रमित हुए हैं, इस तथ्य को बखूबी रेखांकित करती है।

संघ परिवार और उससे जुड़ी ताकतें अंधविश्वास, सांप्रदायिक, परंपरावादी और रूढ़िवादी विश्वासों को बड़े पैमाने पर प्रचारित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं, जिनका मुकाबला विज्ञान आधारित अपने दमदार मीडिया अभियानों के माध्यम से किया जाना है ।

पितृसत्ता को सुदृढ़ करने के लिए धर्म का खुला उपयोग करना ।

अन्य खतरनाक बात यह है कि धार्मिक मान्यताओं का सहारा लेकर रूढ़िवादी विचारों और पितृसता को मजबूत करने के लिए वायरस को लैंगिक आधार देकर क्रोधित देवी के रूप में स्थापित किया जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में एडवा कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्रित की गई जानकारियों अनुसार यह प्रसार जेती से बढ़ रहा है।

राजस्थान में, कुछ प्रसिद्ध मंदिरों को चुपके से खोला गया, सरकार द्वारा पूजा स्थल खोलने पर प्रतिबंध के बावजूद, अफवाहें फैलाई गई कि मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुल गए और लोगों, विशेष रूप से महिलाओं को कोरोना वायरस को शांत करने के लिए वहां प्रार्थना करनी चाहिए। महिलाओं को कुमकुम के पानी में या यूपी में गाय के गोबर में हाथ डुबोने के

लिए कहा गया है और कोरोना माई (देवी) को शांत करने के लिए अपने घरों की दीवारों पर अपनी छाप डाल दी है। बिहार के कुछ हिस्सों में कोरोना माई को शान्त करने के लिए महिलाओं को सिंदूर, बिंदी, मिठाई आदि लेकर आस–पास की नदियों पर जाकर पूजा करने और डुबकी लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जैसा कि वे छठ पूजा के दौरान करती हैं। कुछ स्थानों पर, महिलाएं कोरोना माई को दूर भगाने के लिए बाल खोलकर भूत भगाने जैसा स्वांग कर रही हैं। दुर्भाग्य से यह देखा गया है कि ज्यादातर दलित और पिछड़े परिवारों की महिलाएं इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं। उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में भी नाराज कोरोना देवी को मनाने के लिए प्रचार किया जा रहा है।

एक क्रोधी या खतरनाक देवी की ऐसी धारणाएं जिसे खुश किया जाना चाहिए, पहले भी भारत में देखा गई हैं । छोटे चेचक को महिला देवी के साथ जोड़ा गया है, उदाहरण के लिए तमिलनाडु में मारियामा, और चेचक ही माता, अम्मा, अम्माई आदि के रूप में जाना जाता था, क्योंकि चिकन पॉक्स, खसरा आदि को अक्सर आज भी माता कहा जाता है । इसका एक हिस्सा प्राचीन अर्ध–धार्मिक मान्यताओं से निकला है, लेकिन इसकी भी गहरी जड़ें पितृसत्तात्मक संस्कृति और विचारधाराओं से उपजी हैं जो महिलाओं को बुरी, खतरनाक और शक्ति की भूखी आदि लक्षण बताकर उन्हें चुड़ैल, डायन आदि के रूप में घोषित करती हैं।

तेलंगाना में, संघ परिवार अक्सर महिलाओं के नेतृत्व में प्रभात फेरियां निकाल रहा है। इसके माध्यम से यह प्रचार किया जा रहा है कि कोविड महामारी ने इसलिए फैल रही है क्योंकि महिलाओं ने पूजा और अन्य संस्कारी या पारंपरिक प्रथाओं को करना बंद कर दिया है। उन्हें फिर से शुरू करने के लिए बुला रहे हैं ताकि कोरोना वायरस को दूर किया जा सके। इरादा स्पष्ट रूप से घर के चारों ओर खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर महिलाओं के लिए तैयार की गई एक अधीन की भूमिका के साथ पारंपरिक पितृसत्तात्मक संस्कृति को मजबूत करने का है।

ओडिशा में संघ परिवार समर्थक संगठन प्रचार कर रहे हैं कि मंदिरों को बंद नहीं किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी क्योंकि कोर्ट मुस्लिम और ईसाई समर्थक है। वास्तव में, लगभग सभी धार्मिक संप्रदायों के पूजा स्थलों को संबंधित धार्मिक संस्थाओं द्वारा स्वयं और सरकारी दिशा–निर्देशों अनुसार बंद रखा गया है। जहां ऐसा नहीं हुआ है या शारीरिक दूरी रखने और हाथों की सफाई करने का पालन किए बिना भीड़ एकत्रित हुई हैं, वहां कोविड–19 मामलों में वृद्धि हुई है। कोई भी तर्कसंगत और निष्पक्ष व्यक्ति यह बता देगा कि समस्या धर्म विशेष के साथ नहीं है, बल्कि अपनाए गए तरीकों के साथ है। रूढ़िवादी ताकतें जानबूझकर सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों को हवा दे रही हैं जबकि इस समय में विज्ञान और तर्कसंगत विचार का अवमूल्यन और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करने की जिम्मेदारी से सरकारों का विचलन सभी को विचलित कर रहा है ।

इस संदर्भ में, एडवा और एआईपीएसएन रूढ़िवादी ताकतों द्वारा फैलाए जा रहे अंधविश्वासों और तर्कहीन मान्यताओं के प्रचार का मुकाबला करने के लिए 23 जुलाई 2020 से संयुक्त अभियान शुरू करेंगे । हम कैप्टन लक्ष्मी सहगल जैसी महान सेनानियों से प्रेरणा लेते हुए लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ व विज्ञान के साथ खड़ा करने के लिए काम करेंगें। इस अभियान की मांग है कि संविधान में निहित वैज्ञानिक सोच को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाए। यह अभियान सरकार और प्रतिक्रियावादी ताकतों द्वारा हमें पीछे ले जाने के प्रयासों का विरोध करेगा और एक अग्रगामी, लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक न्याय, आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक सोच के मूल्यों को बनाए रखेगा।

एडवा और एआईपीएसएन का यह संयुक्त अभियान 23 जुलाई से 20 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय वैज्ञानिक सोच दिवस तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस काले दिन अंधविश्वास विरोधी आंदोलन के नेता डॉ नरेंद्र दाभोलकर की दक्षिणपंथी रूढ़िवादी ताकतों द्वारा हत्या कर दी गई थी।